

Dr.Raman Kumar Thakur

Assistant professor (Guest)
Department of Economics,
D.B.College, Jaynagar ,Madhubani.
L.N.M.U.DARBHANGA.

Class:- B.A.part-2(Hons)

Date:- 23 May 2020

TOPIC:- " नियोजन काल में भारत का औद्योगिक विकास "

7). सातवीं पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक विकास(1985-90) (Seventh five year plan and Industrial Development,1985-90):- सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी की उन्नति करके उद्योगों की उत्पादकता के स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया गया। सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता , खाद्यान्न के उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विकास स्थापित करने के लिए था।

कुल मिलाकर सातवीं योजना के काल में औद्योगिक विकास दर लगभग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रही। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन में हुई वार्षिक वृद्धि दर 8.5% थी जो कि 8.3% के निर्धारित लक्ष्य से थोड़ी अधिक हुई थी। इस योजना में कुल 2,18,730 करोड़ रुपए में से 13.4% औद्योगिक क्षेत्र में व्यय किए गये। उद्योगों व खनिज पर 25,971 करोड़ रुपये, लघु उद्योगों पर 3,249 करोड़ रुपया व्यय किया गया ।

8). आठवीं पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक विकास (1992-97) (Eighth five year plan and industrial Development):- आठवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास को एक सहारा मिला और विदेशी कर्ज दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए .इसी बीच भारत 1, जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। इस योजना को आर्थिक विकास के संदर्भ में राव-मनमोहन मॉडल ,के रूप में जाना जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण का दौर आरंभ हुआ जिसमें वर्ष 1991 में प्रस्तुत उदारीकृत औद्योगिक नीति के अधीन देश में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल देकर अधिक तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों को विकसित करने की रणनीति अपनाई गई। आठवीं योजना में औद्योगिक विकास का वार्षिक लक्ष्य 8.2 % रखा गया । वास्तविक औसत वार्षिक उपलब्धि 7.3% रही।

9). नवमी पंचवर्षीय योजना एवं औद्योगिक विकास(1997-2002) (Ninth five year plan and industrial Development,1997-2002) :-

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में भारत में तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी, घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता, जैसे उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नवमी योजना में औद्योगिक विकास दर का वार्षिक लक्ष्य 8.0% रखा गया था किंतु वास्तविक वार्षिक दर केवल 5.0% ही रही। नवमी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत छोटे-बड़े उद्योग एवं खनिज संबंधी विकास कार्यक्रमों के लिए 69,972 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया जो आठवीं योजना के इस मद के आबंटन से डेढ़ गुना अधिक था इस योजना में अन्य क्षेत्रों की तुलना में उद्योग को दी गई प्राथमिकता काफी नीचे थी।